जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष/फैक्स : 01334–226695, मोबाइलः 9412074595

दिनांक : 14.02.2018

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत एवं सीडीओ स्वाती भदौरिया की उपस्थिति में प्रभारी सचिव भारत सरकार श्रीमती ज्योत्सना सिटलिंग के समक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में नीति आयोग के निर्देशों के क्रम में जिले में पिछड़े आंकड़ों पर अपनी प्रजेंटशन दी।

भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के दो जिलों हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, फाइनेंशियल इंक्लुजन, रोजगारपरक कौशल विकास, मूलभूत निर्माण की दृष्टि से अति पिछड़े जनपदों की श्रेणी में रखा है। जिले को इन सभी श्रेणियों सुधार करने के उद्देश्य से नीति आयोग की ओर से प्रभारी सचिव भारत सरकार ने जिलाधिकारी एवं सीडीओ से जिले की प्रगति में आ रही बाधाओं और उनके समाधान के लिए इन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से रियल टाइम मॉनिटरिंग कराये जाने के निर्देश दिये थे। निर्देशों के क्रम में सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयध्यक्षों ने जनपद के पिछड़ने के कारणों, प्रगति में आ रही चुनौतियों व सुधार की दिशा में किये जाने वाले उपायों सहित अपनी प्रजेंटेशन प्रभारी सचिव भारत सरकार श्रीमती ज्योत्सना सिटलिंग के समक्ष प्रस्तुत की।

श्रीमती सिटलिंग ने कहा कि सभी विभाग अपने लक्ष्य, एचीवमेंट के वास्तविक अद्यतन आंकड़े ही प्रजेंटेशन में प्रस्तुत किये गये। प्रभारी सचिव श्रीमती ज्योत्सना ने सभी विभागों की प्रजेंटेशन देखकर अधिकारियों को सम्बोधित किया कि हरिद्वार जिले को अति पिछड़े जिलो की श्रेणी से निकालने के लिए भारत सरकार, उत्तरखण्ड शासन जिलाधिकारी एवं सीडीओ हरिद्वार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को टीम बनकर काम करना है। सभी का लक्ष्य हरिद्वार की उन्नति और विकास है। सभी व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से इसमें अपना योगदान देंगे। जिले की समस्याओं और कमजोरियों को छुपाकर नहीं सामने रखकर समाधान तलाशने हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी केंद्र के समक्ष अपनी समस्या रखने में सबसे अहम कड़ी हैं। अपने स्तर से सुधार के लिए योजना बनाये व समय–समय पर अवगत करायें।

मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री आरडी शर्मा ने बताया कि कक्षा आठ के बाद विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक होने के कारण आंकड़े खराब हैं, कारण बताते हुए कहा कि कक्षा आठ के बाद भोजन, पुस्तक, गणवेश की व्यवस्था निःशुल्क न होने की वजह से भी कमजोर आय वर्ग के छात्र आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं करते इसके परिवार द्वार इन छात्रों को आय अर्जित करने के लिए योग्य समझ लिया जाना भी बड़ी समस्या है। वहीं सरकारी विद्यालयों के छात्रों का गणित, अंग्रेजी व कम्प्यूटर में पिछड़ने के कारणो में सभी विद्यालयों में गणित के शिक्षको का तैनात न होना, अन्य विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी। सचिव ने जिले के सभी विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की संख्या एवं योग्यता का विस्तृत विवरण भी 25 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मदरसा एवं आईटीआई के छात्रों की समक्षता एवं मान्यता भी राज्स सरकार से स्पष्ट करने की बात कही।

सीएमओ अशोक कुमार गैरोला ने गर्भवती महिलाओं के पंजिकरण के डाटा संकलन का प्रतिशत खराब होने के कारण बताते हुए कहा कि उक्त डाटा संकलन करने का कार्य आशा और एएनए द्वारा किया जाता है। जिले में प्रति हजार की आबाद पर एक आशा कार्य करती है, जिसके हिसाब से हमारे पास 2100 आशायें होनी चाहिए जिनके सापेक्ष 1400 आशायें ही कार्य कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में आशाओं की कमी है। एएनएम और आशाओं के पदों को बढ़ाने व भर्तिया करने की मंजूरी उत्तरखण्ड शासन और एनएचम से ही सम्भव है। प्राइवेट चिकित्सालयों में प्रसव कराने के कारण भी, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं, जन्म–मृत्यु दर, आदि के वास्तविक डाटा संकलन नहीं हो पाता है। सरकारी चिकित्सायलयों से बचाने का एक मुख्य कारण लेबर रूम में चिकित्सकों का आदर्श व्यवहार में कमी पाया जाना भी बताया। जिस पर सचिव ने सभी गायनिक को स्पष्ट निर्देश देकर मनयोग से कार्य करने के निर्देश जारी किये जाने तथा जिलाधिकारी के स्तर से सभी निजि चिकित्सालयों को उनके यहां होने वाली डिलिवरी की मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित करने की बात कही।

कृषि एवं उद्यान पशु कल्याण, आईसीडीएस, बेसिक इंफ्रास्टक्चर, कौशल विकास के लिए विभागीय अधिकारियों ने अपनी प्रजेंटेशन सचिव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।